माननीय न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान के समक्ष

बलविंदर कुमार - *याचिका*

बनाम

मेसर्स आरएन हाइवेज (पी) लिमिटेड - *प्रतिवादी*

2018 का सीआरएम-एम नंबर 37409

अगस्त 17, 2018

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 482 - भारतीय दंड संहिता, 1860 - धारा 406 - कॉर्पोरेट आपराधिक दायित्व - प्रत्यावर्ती दायित्व - प्रतिवादी-शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता, एचडीएफसी बैंक के वसूली प्रबंधक के खिलाफ शिकायत दायर की - बैंक को अभियुक्त के रूप में नहीं रखा गया - बैंक से प्राप्त ऋण - बैंक द्वारा ली गई मशीन का कब्जा - बैंक की ओर से समझौता ज्ञापन - विचित्र देयता यदि कोई बैंक की है, शिकायतकर्ता को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि अभियुक्त को संपत्ति या संपत्ति पर प्रभुत्व सौंपा गया था - ऐसे व्यक्ति ने बेईमानी से उस संपत्ति का दुर्विनियोजन किया या अपने स्वयं के उपयोग में परिवतत किया या बेईमानी से संपत्ति का उपयोग या निपटान किया और इस तरह का दुर्विनियोजन, परिवर्तन या निपटान विधि के किसी भी निर्देश का उल्लंघन था।

यह निर्णीत किया गिया है कि याचिकाकर्ता बैंक का कर्मचारी है और बैंक को शिकायत में आरोपी के रूप में नहीं रखा गया है। शिकायतकर्ता के अपने मामले के अनुसार, उसने बैंक से ऋण प्राप्त किया था और उसे चुकाने में विफल रहने के बाद, बैंक द्वारा मशीन का कब्जा ले लिया गया था। इसके बाद ही, जब पक्षों के बीच कुछ समझौते के लिए बातचीत हुई और उनके बीच समझौता ज्ञापन पर सहमति बनी, तो याचिकाकर्ता, बैंक का एक अधिकारी होने के नाते, बैंक की ओर से उस पर हस्ताक्षर किया था और इसलिए, प्रत्यावर्ती देयता, यदि कोई हो, बैंक की है, जो शिकायत में अभियुक्त नहीं है।

(14 (ए) के लिए)

आगे कहा गया कि शिकायत में कोई आरोप नहीं है कि याचिकाकर्ता उस यार्ड का प्रभारी है, जहां मशीन पड़ी है और यहां तक कि कोई आरोप नहीं है कि याचिकाकर्ता ने मशीन के महत्वपूर्ण हिस्सों को हटा दिया था। शिकायत में या शिकायतकर्ता के बयान में इस तरह के किसी भी आरोप के अभाव में, याचिकाकर्ता को अकेले आईपीसी की धारा 406 के तहत अपराध करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, खासकर जब बैंक को आरोपी के रूप में नहीं रखा गया हो।

(14 (बी) के लिए)

आगे कहा गया कि अन्यथा भी, शिकायत के अवलोकन से, आपराधिक विश्वासघात का अपराध नहीं बनता है।

(14 (सी) के लिए)

इसके अलावा, शिकायतकर्ता को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि अभियुक्त को संपत्ति सौंपी गई

थी या संपत्ति पर प्रभुत्व सौंपा गया था; दूसरा, कि ऐसे व्यक्ति ने बेईमानी से उस संपत्ति का दुरुपयोग किया है या अपने स्वयं के उपयोग में परिवर्तित किया है या बेईमानी से संपत्ति का उपयोग या निपटान किया है या जानबूझकर किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए पीड़ित किया है; और तीसरा, इस तरह का दुर्विनियोजन, रूपांतरण, उपयोग या निपटान कानून के किसी भी निर्देश का उल्लंघन था, जिसमें इस तरह के ट्रस्ट का निर्वहन किया जाना है या किसी कानूनी अनुबंध का, जिसे व्यक्ति ने ट्रस्ट के निर्वहन को छूते हुए बनाया है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आरोप नहीं है कि उसे मशीन सौंपी गई थी, जिसे बैंक ने अपने कब्जे में ले लिया था और यह शिकायतकर्ता का भी मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता को संपत्ति पर प्रभुत्व सौंपा गया था।

(14 (डी) के लिए)

आगे कहा गया कि शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ता के बीच प्राथमिक विवाद मशीन की वापसी के संबंध में है, जिस स्थिति में, उसका कब्जा लिया गया था और इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने पहले ही अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए एक सिविल मुकदमा दायर किया था, जिसे पहली बार में खारिज कर दिया गया है और इसलिए, मुख्य रूप से, विवाद सिविल प्रकृति का है, चूंकि शिकायतकर्ता अनिवार्य निषेधाज्ञा की राहत का दावा कर सकता है और साथ ही कानून के अनुसार बैंक से मुआवजे की मांग कर सकता है।

(14 (ई) के लिए)

आगे कहा गया कि प्रतिवादी के वकील द्वारा उठाए गए तर्क कि याचिकाकर्ता के पास सत्र न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर करने का वैकल्पिक उपाय है, इस स्तर पर, जब वर्तमान याचिका पिछले 04 वर्षों से लंबित है और कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी, पर विचार नहीं किया जा सकता है।

(14 (एफ) के लिए)

आगे कहा गया कि यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता और बैंक के बीच विवाद सिविल गलत के रूप में प्रमुख है और इसलिए, याचिकाकर्ता की ओर से बैंक का एक अधिकारी होने के नाते कार्य एक आपराधिक अपराध का गठन नहीं करता है।

(14 (जी) परोसता है)

याचिकाकर्ता के वकील ए.डी.एस.

राघव गुलाटी, अधिवक्ता, भूपिंदर घई के लिए, अधिवक्ता, प्रतिवादी के लिए।

ARVIND SINGH SANGWAN, J. (ORAL)

(1) इस याचिका में अनुरोध 05.06.2008 की आपराधिक शिकायत संख्या 11154 को रद्द करने के लिए है, जिसका शीर्षक आरएन हाईवे (पी) लिमिटेड बनाम बलविंदर सिंह और अन्य (अनुलग्नक पी - 1) है और सम्मन आदेश दिनांक 24.08.2009 (अनुलग्नक पी -2), जिसके माध्यम से याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 406 (संक्षेप में 'आईपीसी') के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया गया है।

(2) मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी-शिकायतकर्ता (इसके बाद 'शिकायतकर्ता' के रूप में संदर्भित) ने याचिकाकर्ता बलविंदर कुमार, एचडीएफसी बैंक के रिकवरी मैनेजर (संक्षिप्त 'बैंक') के साथ जेपी

सिंह, क्षेत्रीय प्रबंधक, राजेश भाटिया, प्रबंधक कानूनी प्रकोष्ठ और एक तरुण लिखा, बैंक के प्रबंधक, शाखा सेक्टर -8, चंडीगढ़ के खिलाफ धारा 390 के तहत उपरोक्त शिकायत दायर की। 392, 403, 406, 420, 424, 426, 427 आईपीसी के साथ आरोप लगाया गया है कि शिकायतकर्ता आरएन हाइवेज प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक है और दिनांक 16.05.2008 के संकल्प के आधार पर शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत है। शिकायतकर्ता-कंपनी ने बैंक से ऋण/वित्त का लाभ उठाकर एक मशीन टाटा हिताची एक्स-110 खरीदी थी। बाद में, शिकायतकर्ता-कंपनी की वित्तीय समस्या के कारण, ऋण राशि की किस्तों का भुगतान नहीं किया जा सका और 30.01.2008 को, याचिकाकर्ता ने शिकायत में नामित अन्य अभियुक्तों, जो बैंक के कर्मचारी थे, के साथ उक्त मशीन को लापरवाह तरीके से अपने कब्जे में ले लिया था और इसे उनकी देखरेख में स्टॉक यार्ड में रखा गया था। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जहां सुलह के प्रयास किए गए। अभियुक्त व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता के प्राधिकृत प्रतिनिधि कमल कांत पुरी द्वारा दिनांक 20-08-2006 को दिया गया एक पत्र प्रस्तुत किया जिसमें बैंक से मशीन को अपने कब्जे में लेने का अनुरोध किया गया था। आगे कहा गया है कि कमल कांत पुरी ने कंपनी की संपत्ति का गबन किया था। बाद में, बैंक और शिकायतकर्ता के बीच एक समझौता ज्ञापन किया गया और समझौते (अनुबंध पी-3) के अनुसार, शिकायतकर्ता ने ऋण राशि के लिए पूर्ण और अंतिम भुगतान के रूप में 14.03.2008 को बैंक को 13,75,000/- रुपये की राशि का भुगतान किया और बैंक ने 17.03.2008 को रसीदें जारी कीं। बैंक ने मशीन के संबंध में 20-03-2008 को मैसर्स संजीव गोयल, स्टॉक यार्ड, पंचकुला को संबोधित करते हुए एक रिलीज मेमो जारी किया। आगे यह कहा गया है कि 21.03.2008 को शिकायतकर्ता को एक इंजीनियर के साथ मशीन का निरीक्षण करने की अनुमति दी गई थी और पाया कि मशीन के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से गायब हैं और लापरवाही से गलत हैंडलिंग के कारण डेंट और क्षति हुई है। नुकसान और कमियों की एक सूची तैयार की गई और याचिकाकर्ता को दी गई, हालांकि, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। बाद में, शिकायतकर्ता ने बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री जेपी सिंह से संपर्क किया और दिनांक 03.04.2008 को एक शिकायत दी और शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया गया कि 72 घंटों के भीतर आवश्यक राशि कम कर दी जाएगी। इसके बाद, शिकायतकर्ता-कंपनी ने दिनांक 20.04.2008 को एक नोटिस जारी किया लेकिन आरोपी व्यक्तियों से कोई जवाब नहीं मिला। शिकायत में आगे कहा गया है कि चूंकि शिकायतकर्ता को 30.01.2008 से 7,000 रुपये प्रति दिन की कमाई का नुकसान हो रहा है, जो 7.00 लाख रुपये है, इसलिए यह प्रार्थना की गई थी कि आरोपी को तलब किया जाए और कानून के अनुसार दंडित किया जाए।

(3) शिकायतकर्ता द्वारा अपने प्रारंभिक साक्ष्य का नेतृत्व करने के बाद, जिसमें शिकायतकर्ता CW1 के रूप में उपस्थित हुआ और Ex.C2 के रूप में निपटान को रिकॉर्ड पर साबित किया, ट्रायल कोर्ट ने दिनांक 24.08.2009 (अनुलग्नक P-2) के आक्षेपित आदेश के तहत याचिकाकर्ता को केवल धारा 406 IPC के तहत तलब किया, हालांकि, आरोपी नंबर 2 से 5, बैंक के अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ कोई सम्मन आदेश पारित नहीं किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने निपटान Ex.C2 के खंड 1 और 3 पर भरोसा किया, जहां यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि बैंक मशीन को अपने ट्रस्ट और अच्छी स्थिति में रखेगा और शिकायतकर्ता को उसी अच्छी स्थिति में वापस कर देगा, जिसमें इसे ट्रस्ट में लिया जा रहा है।

(4) यह याचिका वर्ष 2014 में दायर की गई थी और दिनांक 03.11.2014 के आदेश के तहत, ट्रायल कोर्ट के समक्ष आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी।

(5) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि उस समय, जब शिकायतकर्ता द्वारा ऋण प्राप्त किया गया था, याचिकाकर्ता हस्ताक्षरकर्ता नहीं था और वह केवल निपटान Ex.C2 का हस्ताक्षरकर्ता है और उक्त निपटान के जवाब में, बैंक ने शिकायतकर्ता को मशीन का कब्जा सौंपने की पेशकश की है और यह बैंक का प्रत्यावर्ती दायित्व है, जिसने शिकायतकर्ता के साथ समझौता किया है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि शिकायतकर्ता ने मशीन का निरीक्षण किया था और उसके बाद, उसने समझौता किया था और बैंक ने शिकायतकर्ता से लगातार मशीन को कब्जे में लेने का अनुरोध किया था, लेकिन उसने इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता के वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि यहां तक कि शिकायतकर्ता ने अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा दायर किया है, जिसमें बैंक/उसके अधिकारियों को मशीन के कब्जे को सही काम करने की स्थिति में सौंपने का निर्देश देने के लिए एक डिक्री के लिए प्रार्थना की गई है और दिनांक 20.01.2016 के फैसले के तहत, सिविल कोर्ट ने निम्नलिखित टिप्पणियां करके मुकदमा खारिज कर दिया: -

> "वादी ने पीडब्लू -2 अमरिंदर सिंह के साक्ष्य पर भी भरोसा किया है। यद्यपि, जब वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर मिला तो उसने साक्ष्य में अपना शपथपत्र प्रस्तुत किया था, लेकिन प्रतिपरीक्षा के उद्देश्य से पुन गवाह के कठघरे में कदम नहीं रखा और न्यायालय के आदेशों द्वारा वादी के साक्ष्य को बंद कर दिया गया। हालांकि, उन्होंने फिर से खंडन साक्ष्य के दौरान गवाह के कठघरे में कदम रखा, जिस पर प्रतिवादियों के वकील ने जिरह से पहले आपत्ति जताई थी। चूंकि खंडन साक्ष्य में वादी को केवल उन मुद्दों पर साक्ष्य का नेतृत्व करने की अनुमति दी जा सकती है, जिनमें से जिम्मेदारी प्रतिवादियों पर थी, और इसलिए, खंडन साक्ष्य के दौरान उसके हलफनामे को साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा सकता है, खासकर जब वह जिरह के लिए उपस्थित होने में विफल रहा जब वादी के पास सकारात्मक साक्ष्य का नेतृत्व करने का मौका था। अन्यथा भी, उसकी प्रतिपरीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें उसने कहा था कि उसके पास मौके पर या पुलिस स्टेशन में उसकी उपस्थिति के संबंध में कोई सबूत नहीं है जैसा कि उसके द्वारा हलफनामे में उल्लेख किया गया है। उन्होंने वादी द्वारा 30.1.2008 को निष्पादित किए गए किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, जब प्रतिवादी बैंक द्वारा मशीन को जब्त कर लिया गया था। उक्त तारीख पर उपस्थित होने के लिए उन्हें कभी भी वाद में नामित नहीं किया गया है और उनका साक्ष्य वर्तमान मामले में कमी को भरने के लिए केवल एक विचार प्रतीत होता है। इसके अलावा, उन्होंने प्रतिपरीक्षा में विशेष रूप से गवाही दी है कि उनके पास यह दर्शाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि मशीन को कब उठाया गया था और जब बैंक द्वारा 20-3-2008 को इसे जारी करने का आदेश जारी किया गया था, उसकी स्थिति में कोई अंतर था। उन्होंने आगे गवाही दी है कि वह यह नहीं बता सकते कि किसी मशीन या वाहन में कोई यांत्रिक या तकनीकी खराबी है या नहीं। इसलिए, तथ्य यह है कि वादी द्वारा भरोसा किया गया मौखिक साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है और वादी कंपनी के निदेशक मोहिंदर सिंह, जिनके माध्यम से वर्तमान मुकदमा दायर किया गया है, ने गवाह के कठघरे में कदम नहीं रखा है और इस संबंध में वादी के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना है।
>
> वादी के विद्वान वकील द्वारा दस्तावेजों Ex.PE और Ex.PF पर बहुत भरोसा किया गया है। सबसे पहले, यहां यह देखना उचित है कि सबसे पहले इन दस्तावेजों के मूल ने कभी भी

दिन की रोशनी नहीं देखी है और यह एक स्थापित कानून है कि दस्तावेज़ की एक फोटोकॉपी साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है। वादी के विद्वान वकील ने कहा है कि प्रतिवादियों द्वारा Ex.PF के निष्पादन से इनकार नहीं किया गया है। यहां तक कि इस तरह के परिदृश्य में भी उक्त दस्तावेजों की सामग्री साक्ष्य में केवल एक फोटोकॉपी होने के नाते अस्वीकार्य है क्योंकि यह केवल निष्पादन है जिसे स्वीकार किया गया है, लेकिन इसकी सामग्री को प्रतिवादियों द्वारा कहीं भी स्वीकार नहीं किया गया है। इसके अलावा, उक्त दस्तावेज के अवलोकन से कहीं भी यह पता नहीं चलता है कि मशीन उस समय काम करने की स्थिति में थी जब प्रतिवादी बैंक द्वारा 30.1.2008 को इसे जब्त कर लिया गया था। वही केवल इस तथ्य को संदर्भित करता है कि मशीन अच्छी स्थिति में थी। हालांकि, यह एक सापेक्ष शब्द है और यह कहीं भी एक अनुमान नहीं उठाता है कि मशीन उक्त दिन काम करने की स्थिति में थी। इसके अलावा, वादी यह भी साबित करने में विफल रहा है कि प्रतिवादी बैंक द्वारा उसे रिलीज मेमो जारी किए जाने के दिन मशीन काम करने की स्थिति में नहीं थी। जहां तक Ex.PE दस्तावेज का संबंध है, वह भी दस्तावेज की एक फोटोकॉपी है और अन्यथा भी प्रतिवादी बैंक के किसी भी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया है। इसलिए, इन परिस्थितियों में, मेरी सुविचारित राय है कि वादी वाद में लगाए गए आरोपों को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है, और इस तरह, इन दोनों मुद्दों का फैसला वादी के खिलाफ और प्रतिवादियों के पक्ष में किया जाता है।

मुद्दा संख्या 3।

वादी ने अनिवार्य निषेधाज्ञा और इससे हुए नुकसान की वसूली के लिए वर्तमान वाद दायर किया है। हालांकि, वादी योग्यता के आधार पर अपने मामले को साबित करने में विफल रहा है, लेकिन यह विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 9 के प्रावधानों के तहत बनाए रखने योग्य है। इसलिए, इस मुद्दे को वादी के पक्ष में और प्रतिवादियों के खिलाफ तय किया जाता है।

मुद्दा संख्या 4।

वादी ने अनिवार्य निषेधाज्ञा और इससे हुए नुकसान की वसूली के लिए वर्तमान वाद दायर किया है। हालांकि, वाद के मुख्य नोट और राहत खंड में, वादी ने उस राशि का उल्लेख नहीं किया है जिसे वाद में कथित नुकसान के मद्देनजर वसूल करने की मांग की गई है, लेकिन वाद के पैरा नंबर 23 (ii) में, उसने कथित नुकसान को 43,37,500 रुपये तक बताया है। वाद को उसकी संपूर्णता में पढ़ा जाना चाहिए और केवल इसलिए कि वाद के मुख्य नोट और राहत खंड में कोई राशि नहीं लिखी गई है और विशेष रूप से जब कथित नुकसान को उसके द्वारा वाद के पैरा संख्या 23 (ii) में निर्धारित किया गया है, तो विज्ञापन-मूल्यानुसार न्यायालय शुल्क दायर नहीं करने का कोई आधार नहीं है। अतः न्यायालय शुल्क और अधिकारिता के प्रयोजनों के लिए 43,37,500/- रुपये की वसूली की राहत पर वाद का मूल्यांकन किया जाना है। हालांकि, वादी ने केवल 35/- रुपये का न्यायालय शुल्क तय किया है, और वसूली की राशि पर यथामूल्य न्यायालय शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन इसका भुगतान करने में विफल रहा है। इसलिए, इस मुद्दे का फैसला वादी के खिलाफ और प्रतिवादियों के पक्ष

में किया जाता है।

मदद।

इस प्रकार, सुप्रा मुद्दों पर किए गए मेरे निष्कर्षों के मद्देनजर, वादी का मुकदमा विफल हो जाता है और उसी को लागत के रूप में बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है।

(6) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि ऋण की उन्नति, उसके पुनर्भुगतान और मशीन को अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया बैंक द्वारा की गई थी, जिसे आरोपी के रूप में नहीं माना जाता है और याचिकाकर्ता को सौंपी गई एकमात्र भूमिका यह थी कि वह समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षरकर्ता था। आगे यह तर्क दिया गया है कि ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता को केवल आईपीसी की धारा 406 के तहत तलब किया है और बैंक के किसी अन्य अधिकारी को इस संबंध में नहीं बुलाया गया था। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया है कि शिकायत और शिकायतकर्ता के बयान के अवलोकन से, याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है।

(7) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने ***अनूप सरमाह*** *बनाम* ***भोलानाथ शर्मा और अन्य*** पर भरोसा किया है [1] जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार आयोजित किया है: -

"उपरोक्त के मद्देनजर, कानून को संक्षेप में कहा जा सकता है कि किराया खरीद के एक समझौते में, खरीदार फाइनेंसर/वित्तीय संस्थान की ओर से केवल एक ट्रस्टी/बेली रहता है और स्वामित्व बाद वाले के पास रहता है। इस प्रकार, यदि फाइनेंसर द्वारा वाहन जब्त कर लिया जाता है, तो उसके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि वह अपने स्वामित्व वाले सामान को फिर से हासिल कर रहा है।

यदि उपरोक्त तय कानूनी प्रस्ताव के आलोक में मामले की जांच की जाती है, तो हमें आक्षेपित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई ठोस कारण नहीं दिखता है। याचिका में दम नहीं है और तदनुसार इसे खारिज कर दिया गया है।

(8) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने ***शरद कुमार सांघी*** *बनाम* ***संगीता राणे*** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया [2] है कि जहां आरोप प्रबंध निदेशक या कंपनी के किसी अधिकारी से संबंधित हैं और अधिकारियों के खिलाफ किसी विशिष्ट आरोप के अभाव में, कंपनी को फंसाने के बिना शिकायत केवल अधिकारियों के खिलाफ दायर की गई है, शिकायत रद्द की जा सकती है।

(9) विद्वान वकील ने ***एसके अलघ*** *बनाम* ***उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य***[3] पर भी भरोसा किया है, जहां कंपनी के खिलाफ धारा 406 आईपीसी के तहत आरोप लगाए गए थे और कंपनी के प्रबंध निदेशक के खिलाफ शिकायत दायर की गई थी और कंपनी को आरोपी के रूप में नहीं रखा गया था, कार्यवाही रद्द कर दी गई थी।

---

[1] 2013 (1) आरसीआर (सीआरएल) 62

[2] 2015 (2) आरसीआर (सीआरएल) 120

[3] 2008 (2) आरसीआर (सीआरएल) 79

(10) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने मैसर्स ***जीएचसीएल कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन ट्रस्ट*** *बनाम* ***मैसर्स इंडिया इंफोलाइन लिमिटेड*** पर भी भरोसा किया है, [4] जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि विश्वास भंग या धोखाधड़ी दोनों नागरिक गलत और साथ ही आपराधिक अपराध हैं और कुछ स्थितियों में, जहां कथित अधिनियम मुख्य रूप से एक नागरिक गलत होगा, ऐसा कृत्य एक आपराधिक अपराध का गठन नहीं करता है।

(11) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने अंत में तर्क दिया है कि ***धारीवाल टोबैको प्रोडकट्स लिमिटेड*** और अन्य *बनाम* ***महाराष्ट्र राज्य और अन्य*** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर, याचिकाकर्ता के पास धारा 397 सीआरपीसी के तहत [5]सम्मन आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर करने का एक उपाय है, फिर भी वैकल्पिक उपाय के रूप में धारा 482 सीआरपीसी के तहत याचिका दायर कर सकता है और धारा 482 सीआरपीसी के तहत दायर याचिका को केवल खारिज नहीं किया जा सकता है इस आधार पर कि पुनरीक्षण का उपाय अभियुक्त व्यक्तियों के लिए उपलब्ध था।

(12) जवाब में, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि शिकायत के अवलोकन से, याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 406 आईपीसी के तहत अपराध बनता है, क्योंकि वह बैंक का प्रतिनिधि होने के नाते, समझौता में प्रवेश किया था और मशीन को अपने विश्वास और अच्छी स्थिति में रखने का वादा किया था। याचिकाकर्ता ने आगे कहा था कि मशीन को उसी अच्छी स्थिति में लौटाया जाएगा, जिसमें इसे विश्वास में लिया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि समझौता ज्ञापन के अनुसरण में, शिकायतकर्ता ने निपटान का अपना हिस्सा निभाया है और पूरी ऋण राशि का भुगतान किया है और जब वह 21.03.2008 को मशीन का निरीक्षण करने गया था, तो उसने पाया कि मशीन के महत्वपूर्ण हिस्से गायब थे और कुछ हिस्सों को कबाड़ से बदल दिया गया था और मशीन को नुकसान हुआ था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि बैंक द्वारा नोटिस जारी करने और आश्वासन दिए जाने के बावजूद, मशीन को उसकी मूल स्थिति में बहाल नहीं किया गया था और इसलिए, धारा 406 आईपीसी के तहत प्रथम दृष्टया अपराध बनता है और ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सही तरीके से तलब किया है, क्योंकि वह बैंक का आधिकारिक प्रभारी था, जिसके प्रतिनिधित्व पर, शिकायतकर्ता ने पूरी ऋण राशि जमा कर दी, यह विश्वास करते हुए कि मशीन को उसकी मूल स्थिति में बहाल कर दिया जाएगा।

(13) विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि आज तक, 10 साल से अधिक की अवधि बीत जाने के बावजूद, मशीन अभी भी बैंक के पास पड़ी हुई है और शिकायतकर्ता ने पहले ही सिविल कोर्ट के 20.01.2016 के फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर कर दी है, जिसके माध्यम से शिकायतकर्ता द्वारा दायर अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए सिविल मुकदमा खारिज कर दिया गया था।

(14) पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुनने के बाद, मुझे निम्नलिखित कारणों से वर्तमान याचिका में योग्यता मिलती है: -

(a) बेशक, याचिकाकर्ता बैंक का कर्मचारी है और बैंक को शिकायत में आरोपी के रूप में नहीं दिखाया गया है। शिकायतकर्ता के अपने मामले के अनुसार, उसने बैंक से ऋण प्राप्त

---

[4] 2013 (2) आरसीआर (सा.रा.) 519

[5] 2009 (1) आरसीआर (सीआरएल) 677

किया था और उसे चुकाने में विफल रहने के बाद, बैंक द्वारा मशीन का कब्जा ले लिया गया था। इसके बाद ही, जब पक्षों के बीच कुछ समझौते के लिए बातचीत हुई और उनके बीच समझौता ज्ञापन पर सहमति बनी, तो याचिकाकर्ता, बैंक का एक अधिकारी होने के नाते, बैंक की ओर से उस पर हस्ताक्षर किया था और इसलिए, प्रत्यावर्ती देयता, यदि कोई हो, बैंक की है, जो शिकायत में अभियुक्त नहीं है।

(b) शिकायत में कोई आरोप नहीं है कि याचिकाकर्ता उस यार्ड का प्रभारी है, जहां मशीन पड़ी है और यहां तक कि यह भी आरोप नहीं है कि याचिकाकर्ता ने मशीन के महत्वपूर्ण हिस्सों को हटा दिया था। शिकायत में या शिकायतकर्ता के बयान में इस तरह के किसी भी आरोप के अभाव में, याचिकाकर्ता को अकेले आईपीसी की धारा 406 के तहत अपराध करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, खासकर जब बैंक को आरोपी के रूप में नहीं रखा गया हो। इसलिए, ***शरद कुमार सांघी*** के मामले (सुप्रा) और ***एसके अलघ*** के मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर , याचिकाकर्ता का अभियोजन बनाए रखने योग्य नहीं है।

(c) अन्यथा भी, शिकायत के अवलोकन से, आपराधिक विश्वास भंग का अपराध नहीं बनता है। ***अशोक बसाक*** *बनाम* ***महाराष्ट्र राज्य और अन्य***, **2014 (4) आरसीआर (सीआरएल) 789** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि आपराधिक विश्वास भंग के अपराध को साबित करने के लिए, शिकायतकर्ता को संतुष्ट होना चाहिए कि अभियुक्त को संपत्ति सौंपी गई थी या संपत्ति पर प्रभुत्व सौंपा गया था; दूसरा, कि ऐसे व्यक्ति ने बेईमानी से उस संपत्ति का दुरुपयोग किया है या अपने स्वयं के उपयोग में परिवर्तित किया है या बेईमानी से उपयोग या निपटान किया है संपत्ति का या जानबूझकर ऐसा करने के लिए किसी भी व्यक्ति को पीड़ित किया; और तीसरा, इस तरह के दुरुपयोग, रूपांतरण, उपयोग या निपटान कानून के किसी भी निर्देश के उल्लंघन में था, जिसमें इस तरह के ट्रस्ट का निर्वहन किया जाना है या किसी कानूनी अनुबंध का, जिसे व्यक्ति ने ट्रस्ट के निर्वहन को छूने के लिए बनाया है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आरोप नहीं है कि उसे मशीन सौंपी गई थी, जिसे बैंक ने अपने कब्जे में ले लिया था और यह शिकायतकर्ता का मामला भी नहीं है कि याचिकाकर्ता को संपत्ति पर प्रभुत्व सौंपा गया था। शिकायत में दूसरी और तीसरी शर्त का भी खुलासा नहीं किया गया है क्योंकि मशीन बैंक के यार्ड में पड़ी है और इसलिए, याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता की किसी भी संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग नहीं किया है, क्योंकि वह बैंक के एक अधिकारी के रूप में अपनी नौकरी का निर्वहन कर रहा था और उसके खिलाफ केवल आरोप है कि वह समझौता ज्ञापन के हस्ताक्षरकर्ता थे।

(d) ***वीवाई जोस*** और अन्य *बनाम* ***गुजरात राज्य और अन्य***, **2009 (1) आरसीआर (सीआरएल) 869** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर, शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ता के बीच प्राथमिक विवाद मशीन की वापसी के संबंध में है, जिस स्थिति में

इसका कब्जा लिया गया था और इसके बावजूद, शिकायतकर्ता ने पहले ही अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए एक सिविल मुकदमा दायर किया था, जिसे पहली बार में खारिज कर दिया गया है और इसलिए, मुख्य रूप से, विवाद सिविल प्रकृति का है, क्योंकि शिकायतकर्ता अनिवार्य निषेधाज्ञा की राहत का दावा कर सकता है और साथ ही कानून के अनुसार बैंक से मुआवजे की मांग कर सकता है।

(e) हालांकि याचिकाकर्ता ने चार अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाए हैं, हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने केवल याचिकाकर्ता को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया है और शिकायतकर्ता ने अन्य अधिकारियों के खिलाफ सम्मन आदेश को चुनौती नहीं दी है, जिनके खिलाफ याचिकाकर्ता के खिलाफ समान आरोप हैं। अन्यथा भी, हालांकि शिकायतकर्ता ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की है, ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता को केवल धारा 406 आईपीसी के तहत बुलाया है और शिकायत के अवलोकन से, धारा 406 आईपीसी की सामग्री नहीं बनती है, क्योंकि बैंक ने कानून के अनुसार वाहन को वापस ले लिया था।

(f) प्रतिवादी के वकील द्वारा उठाए गए तर्क कि याचिकाकर्ता के पास सत्र न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर करने का वैकल्पिक उपाय है, इस स्तर पर, जब वर्तमान याचिका पिछले 04 वर्षों से लंबित है और कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी, पर विचार नहीं किया जा सकता है, अन्यथा भी, ***धारीवाल टोबैको प्रोडक्ट्स लिमिटेड*** के मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को देखते हुए, वर्तमान याचिका केवल इसी आधार पर खारिज नहीं की जा सकती।

(g) ***मैसर्स जीएचसीएल कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन ट्रस्ट*** के मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता और बैंक के बीच विवाद प्रमुख रूप से सिविल गलत है और इसलिए, याचिकाकर्ता की ओर से बैंक का अधिकारी होने के नाते कार्य एक आपराधिक अपराध नहीं है।

(15) ऊपर बताए गए कारणों के लिए, वर्तमान याचिका की अनुमति दी जाती है। 05.06.2008 की आपराधिक शिकायत संख्या 11154 ***आर.एन.***(ग) *माननीय उच्चतम न्यायालय* ने ***बलविंदर सिंह एवं अन्य*** के विरुद्ध मामले की सुनवाई करते हुए दिनांक 24-08-2009 (संलग्नक पी-2) के सम्मन आदेश को रद्द किया है।

J.S. Mehndiratta

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय केवल वादकर्ता के सीमित उपयोग के लिए है ताकि व ह इसेअपनी भाषा में समझ सके और इसका उपयोग किसी अन्य उद्दे श्य के लिए नहींकिया जा सकता है। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी न्यायिक और प्रशासनिकउद्देश्यों के लिए मान्य होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिएउपयुक्त रहेगा।

हिमानी सागर
प्रशिक्षित न्याय अधिकारी, हरियाणा